



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

निर्यात संवर्धन मिशन: भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत ढांचा

6 दिसंबर, 2025

मुख्य बिंदु

- सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से एमएसएमई और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए, ₹25,060 करोड़ के साथ निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी।
- डीजीएफटी के माध्यम से एकीकृत, डिजिटल रूप से संचालित ढांचा, तेज़ और पारदर्शी वितरण के लिए कई निर्यात-समर्थन योजनाओं का स्थान लेता है।
- निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, निर्यातकों को एकीकृत वित्तीय और बाज़ार-तैयारी सहायता प्रदान करते हैं।
- ₹20,000 करोड़ की ऋण गारंटी और आरबीआई के राहत उपायों से तरलता मजबूत होती है और निर्यात ऋण दबाव कम होता है।
- व्यापक-आधारित, समावेशी निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ-प्रभावित क्षेत्रों और गैर-पारंपरिक जिलों से निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रस्तावना

भारत का निर्यात प्रदर्शन देश की आर्थिक रणनीति का केंद्र रहा है, जो रोजगार पैदा करने, विनिर्माण और सेवाओं में विकास को बढ़ावा देने और भारतीय फर्मों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने में मदद करता है। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए, सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी।

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित, मिशन एक प्रमुख ढांचागत सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जो कई निर्यात-समर्थन पहलों को एक एकल, परिणाम-आधारित और डिजिटल रूप से सक्षम ढांचे में विलय करता है। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए ₹25,060 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ, ईपीएम का लक्ष्य भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, आसान व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार करना और सभी क्षेत्रों में वैश्विक बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

एक मिशन क्यों? नीतिगत तर्क

भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को हाल के वर्षों में लक्षित हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित है, जिसमें ब्याज समानता, बाजार तक पहुंचने की पहल और निर्यात-प्रोत्साहन योजनाएं तथा बुनियादी ढांचे का समर्थन शामिल है। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए पहचाने गए प्रमुख कारकों जैसे किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन का समर्थन करना, समन्वित निर्यात ब्रांडिंग और बाजार-पहुंच सुविधा में सुधार करना, और आंतरिक और कम-निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए रसद नुकसान को कम करना के लिए इस मिशन का निर्माण हुआ है।

हाल के निर्यात रुझान एक अधिक समन्वित और डिजिटल रूप से सक्षम समर्थन ढांचे के महत्व को रेखांकित करते हैं जो माल और सेवा दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार-तत्परता को मजबूत कर सकता है।

कई योजनाओं को एकल, डिजिटल रूप से प्रबंधित और परिणाम-लिंकड आर्किटेक्चर में समेकित करके, निर्यात संवर्धन मिशन का लक्ष्य भारत के निर्यातकों को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी समर्थन प्रदान करना है, एक एकीकृत, लचीला और उत्तरदायी ढांचा सुनिश्चित करना जो उभरती वैश्विक व्यापार स्थितियों के साथ संरेखित हो।

संरचना, शासन और वित्तपोषण

ईपीएम 25,060 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ छह वर्षों तक चलेगा जो वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक कवर करेगा। मिशन एक संस्थागत ढांचा है जिसमें वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, निर्यात संवर्धन परिषद कमोडिटी बोर्ड, वित्तीय संस्थान, उद्योग संघ और राज्य सरकारें शामिल हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो व्यापार और सीमा शुल्क प्रणालियों के साथ संरेखित, आवेदन से लेकर अनुमोदन से लेकर वितरण तक, एंड-टू-एंड प्रक्रियाओं

के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा। मिशन अंतर-मंत्रालयी समन्वय, राज्य साझेदारी और डेटा-संचालित निगरानी पर जोर देता है।

दो एकीकृत उप-योजनाएँ: निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा

ईपीएम दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होता है जो एक साथ वित्त और गैर-वित्तीय सक्षमताओं को संबोधित करते हैं:

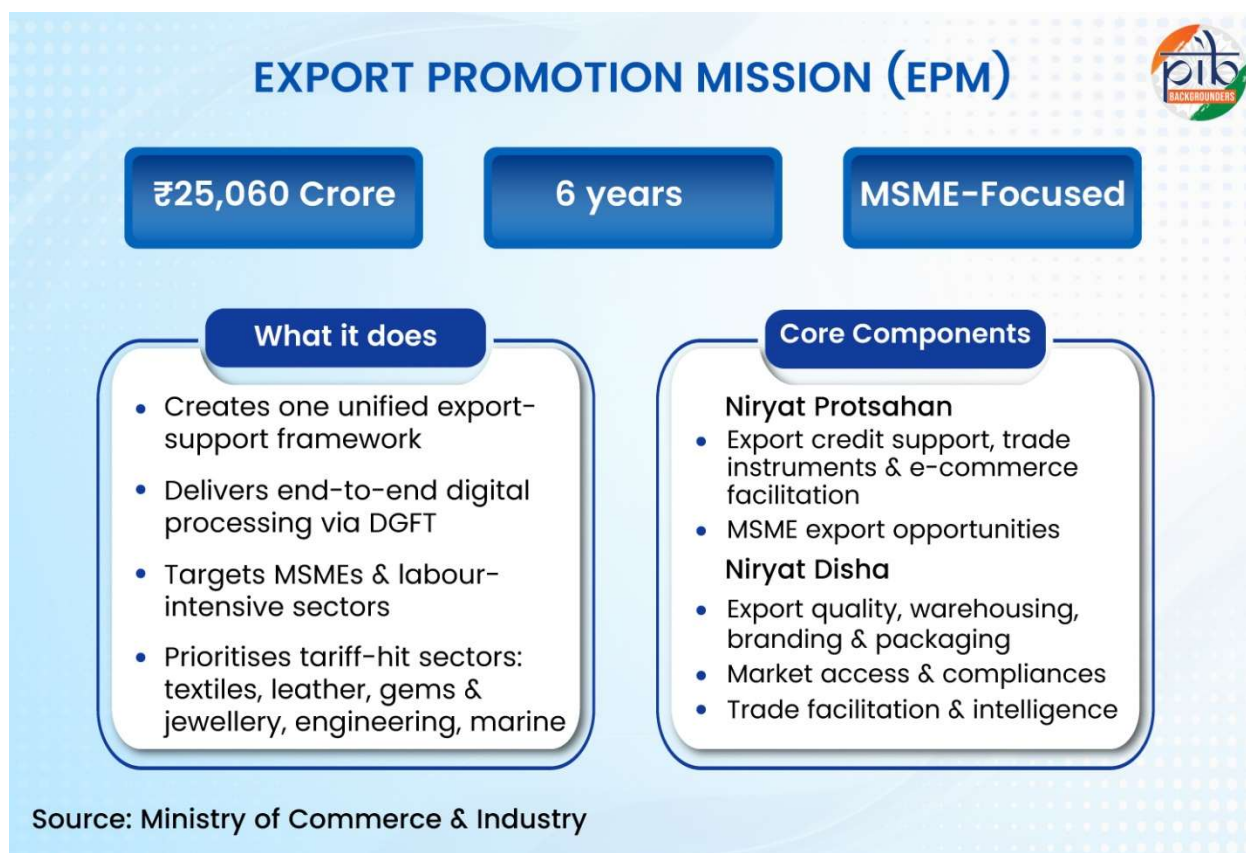
निर्यात प्रोत्साहन (वित्तीय समर्थक) - यह उप-योजना प्री- और पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट पर ब्याज छूट, निर्यात-फैक्टरिंग और डीप-टियर फाइनेंसिंग, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड, निर्यात क्रेडिट के लिए संपार्श्विक समर्थन और नए या क्रेडिट-वृद्धि के लिए संपार्श्विक समर्थन उच्च जोखिम वाले बाजार. जैसे उपकरणों के माध्यम से एमएसएमई निर्यातकों के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है

निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सक्षमकर्ता) - इस उप-योजना का लक्ष्य निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन के लिए समर्थन (परीक्षण, प्रमाणन, ऑडिट), अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग सहायता, व्यापार मेलों और खरीदार-विक्रेता बैठकों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और रसद, दूरस्थ-जिला निर्यातकों के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति, औरक्लस्टर, एसोसिएशन और जिला-स्तरीय सुविधा सेल स्तर पर क्षमता निर्माण के माध्यम से बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।

डिजिटल कार्यान्वयन और निगरानी

ईपीएम की एक प्रमुख विशेषता इसका **समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म** है, जिसके माध्यम से डीजीएफटी एकीकृत, कागज रहित तरीके से आवेदन से लेकर अनुमोदन और वितरण तक सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करेगा। प्लेटफॉर्म को मौजूदा व्यापार प्रणालियों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे मिशन हस्तक्षेपों की तेज़ प्रसंस्करण और पारदर्शी डिलीवरी सक्षम होगी।

मिशन एक परिणाम-आधारित तंत्र है जो वैश्विक व्यापार विकास पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। डिजिटल आर्किटेक्चर समन्वित कार्यान्वयन, परिणाम-लिंकड डिलीवरी और समय पर निरीक्षण का समर्थन



करता है, जो दक्षता, समावेशिता और निर्यात-तत्परता पर मिशन के जोर को रेखांकित करता है।

क्षेत्र और क्षेत्रीय फोकस

ईपीएम वैश्विक शुल्क वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है, विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद, जबकि अन्य उभरते निर्यात क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए लचीलापन बनाए रखता है। मिशन स्पष्ट रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यातकों और श्रम-गहन मूल्य श्रृंखलाओं को लक्षित करता है, जिससे समावेशी पहुंच सुनिश्चित होती है।

निर्यात दिशा घटक के तहत, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति, भंडारण और रसद समर्थन, व्यापार मेलों में भागीदारी, ब्रांडिंग और पैकेजिंग सहायता, और जिला-स्तरीय क्षमता निर्माण जैसे उपायों के साथ, हस्तक्षेप आंतरिक और कम-निर्यात-तीव्रता वाले जिलों की ओर निर्देशित किया जाता है। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत के निर्यात के भौगोलिक विस्तार को व्यापक बनाना और वैश्विक बाजारों में समावेशी भागीदारी को सक्षम करना है।

निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना

मिशन के साथ मिलकर, सरकार ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी (सीजीएसई), एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सहायता में 20,000 करोड़ रुपये तक प्रदान करना। यह योजना वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाएं बढ़ाने के लिए सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।

यह योजना एनसीजीटीसी के माध्यम से 100% भारत सरकार की गारंटी द्वारा, संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट पहुंच और स्वीकृत निर्यात कार्यशील पूंजी सीमा के 20% तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी को सक्षम करके तरलता को मजबूत करती है। 31 मार्च 2026 तक वैध, सरकार के निर्णय से नए निर्यात बाजारों की खोज में सहायता मिलने और भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

विनियामक और केंद्रीय बैंक सहायता (आरबीआई उपाय)

वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बीच निर्यात क्षेत्र में तरलता के दबाव को कम करने के लिए **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)** द्वारा घोषित पूरक कदमों से मिशन की प्रभावशीलता को और भी मजबूती मिली है। नवंबर 2025 में, आरबीआई ने **भारतीय रिजर्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) दिशानिर्देश, 2025** जारी किया, जिसका उद्देश्य ऋण-सेवा तनाव को कम करना और व्यवहार्य निर्यात-उन्मुख व्यवसायों की निरंतरता को बढ़ावा देना है।

आरबीआई द्वारा घोषित प्रमुख उपाय

- पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन** - विनियमित संस्थाएं (आरई) **टर्म-लोन** किस्तों पर अधिस्थगन की पेशकश कर सकती हैं और 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच देय कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) सुविधाओं पर ब्याज को स्थगित कर सकती हैं। ब्याज साधारण-ब्याज के आधार पर, बिना चक्रवृद्धि के अर्जित होगा, और इसे **फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन (एफआईटीएल)** में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे 31 मार्च से 31 मार्च के बीच चुकाया जा सकता है। 30 सितंबर 2026.
- निर्यात क्रेडिट अवधि का विस्तार** - प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए अनुमेय ऋण अवधि को वितरित ऋण के लिए 450 दिनों तक बढ़ा दिया गया है 31 मार्च, 2026 तक।

31 अगस्त, 2025 से पहले निर्यातकों द्वारा प्राप्त पैकिंग ऋण सुविधाओं के लिए, जहां प्रेषण नहीं हो सका, आरईएस घरेलू बिक्री आय या निर्यात अनुबंधों के प्रतिस्थापन सहित किसी भी वैध वैकल्पिक स्रोत से परिसमापन की अनुमति दे सकता है।

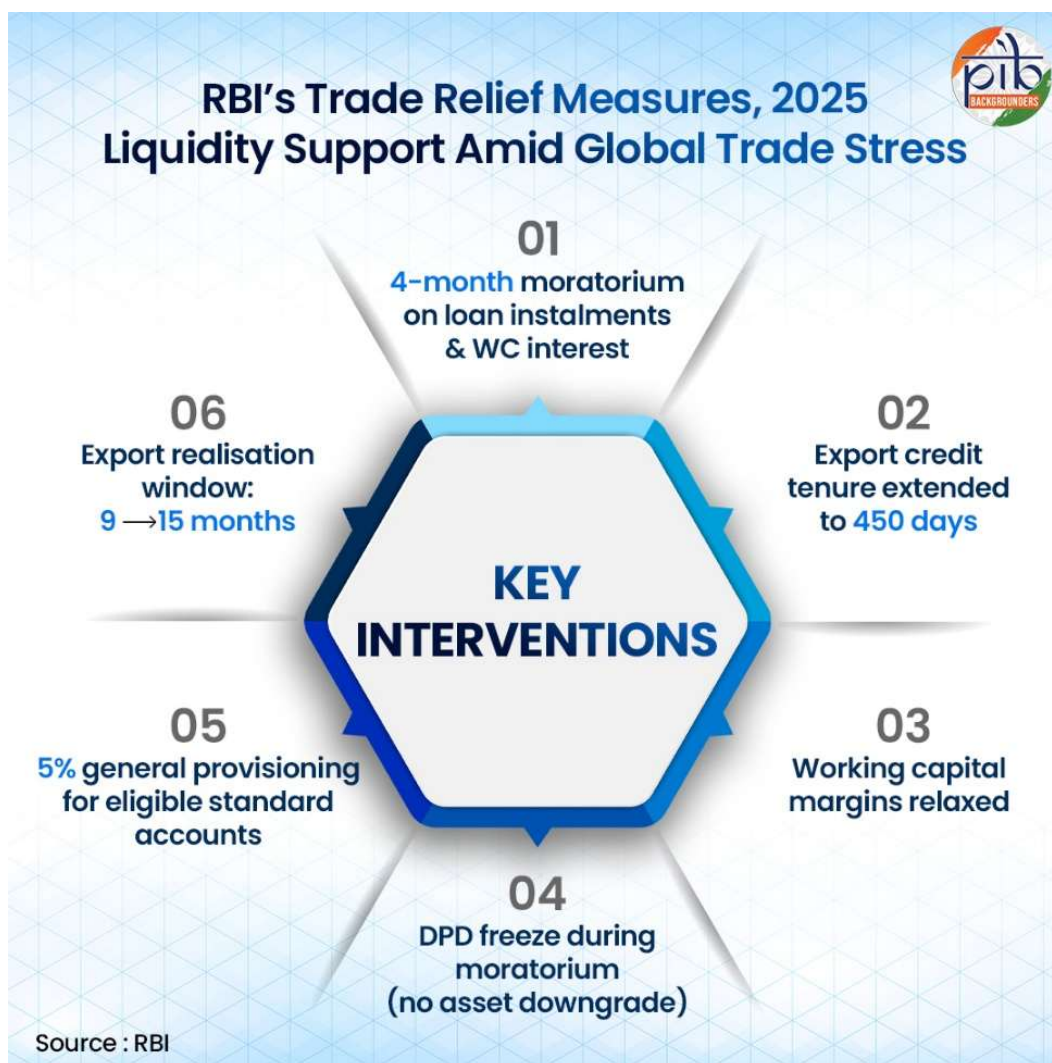
3. कार्यशील पूंजी प्रबंधन में लचीलापन - प्रभावी अवधि के दौरान तरलता बनाए रखने के लिए, आरईएस मार्जिन को कम करके या कार्यशील पूंजी सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन करके ड्राइंग पावर की पुनर्गणना कर सकता है।

4. संपत्ति वर्गीकरण पर विनियामक सहनशीलता - आईआरएसीपी मानदंडों के तहत अधिस्थगन/स्थगन अवधि को पिछले बकाया दिनों (डीपीडी) की गणना से बाहर रखा जाएगा; राहत देना पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा; क्रेडिट ब्यूरो (सीआईसी) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उधारकर्ताओं का क्रेडिट इतिहास अप्रभावित रहे।

5. प्रावधान की आवश्यकता - विनियमित संस्थाओं को पात्र उधारकर्ता खातों पर कम से कम **5 प्रतिशत** का सामान्य प्रावधान करना होगा जो 31 अगस्त 2025 तक मानक थे और जिनके लिए राहत बढ़ा दी गई है।

6. निर्यात वसूली के लिए फेमा छूट - विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 के तहत, निर्यात आय की वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है, और अग्रिम भुगतान के खिलाफ शिपमेंट अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है।

ये विनियामक और राजकोषीय उपाय निर्यातकों को समर्थन का एक एकीकृत ढांचा प्रदान करते हैं - तरलता बनाए रखना, ऋण अनुशासन की रक्षा करना और एक उन्नत निर्यात-पारिस्थितिकी तंत्र के मिशन के लक्ष्य के साथ संरेखित करना।



अपेक्षित परिणाम और व्यापक आर्थिक संबंध

अधिक प्रतिस्पर्धी और लचीला निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए, मिशन को वित्तपोषण, गुणवत्ता मानकों, बाजार पहुंच और संस्थागत क्षमता में मापने योग्य परिणाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक समन्वित, प्रौद्योगिकी-संचालित और उद्योग-उत्तरदायी ढांचा प्रदान करके, ईपीएम व्यापार वित्त, अनुपालन तत्परता और जिला-स्तरीय भागीदारी जैसे क्षेत्रों में समर्थन को मजबूत करता है ।

ईपीएम से अपेक्षा की जाती है:

- एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार
- अनुपालन और प्रमाणन समर्थन के माध्यम से निर्यात-तत्परता बढ़ाएं
- बाज़ार पहुंच, भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग और दृश्यता बढ़ाना

- गैर-पारंपरिक जिलों और क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा दें
- विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं में रोजगार पैदा करें

ये परिणाम राष्ट्रीय उद्देश्यों, निर्यात-आधारित विकास को मजबूत करना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और विकसित भारत @ 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में योगदान देना के अनुरूप हैं। निर्यात समर्थन को समेकित और आधुनिकीकरण करके, मिशन का लक्ष्य भारत को वैश्विक व्यापार में एक लचीला, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी भागीदार बनाना है।



निष्कर्ष

निर्यात संवर्धन मिशन एक सुसंगत, प्रौद्योगिकी-संचालित और समावेशी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक निर्णायक कदम है। राजकोषीय प्रोत्साहन, वित्तीय सुविधा, डिजिटल प्रशासन और नियामक लचीलेपन को एक एकल मिशन-मोड ढांचे में विलय करके, सरकार ने भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली मंच बनाया है। जैसे-जैसे मिशन आरबीआई के राहत उपायों और विस्तारित क्रेडिट गारंटी योजना के साथ आगे बढ़ता है, यह निर्यात-आधारित विकास, एमएसएमई को सशक्त बनाने, बाजारों में विविधता लाने और भारत को वैश्विक वाणिज्य में एक लचीला, विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

पीके/केसी/एनकेएस